Business Bhaskar
New Delhi, 12 June 2012

भारत के लिए अब विदेशी निवेश आसान नहीं : रुचिर शर्मा

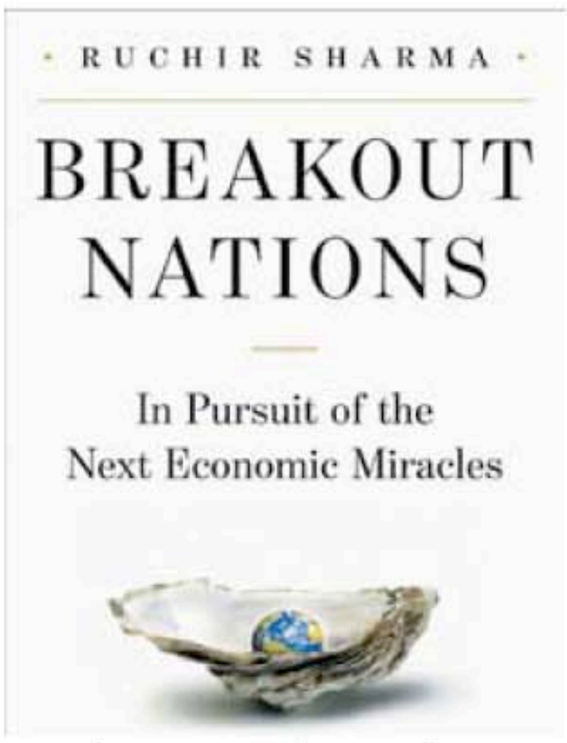

पिछले दिनों मॉर्गेन स्टेनली के इमर्जिंग मार्केट प्रमुख रुचिर शर्मा ने अपनी किताब 'ब्रेकआउट नेशन्स : इन पर्सूट ऑफ द नेक्स्ट इकोनॉमिक मिरेकल्स' की सूची में मौजूदा दौर की कुछ तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाओं को निकाल दिया तो इसकी खासी चर्चा हुई। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है कि क्यों चीन, ब्राजील और रूस जैसी बड़ी और मजबूत इकोनॉमी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी? इसके बजाय उन्होंने, तुर्की, पोलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक जैसे देशों के असाधारण आर्थिक प्रदर्शन की उम्मीद लगाई है। ब्रेकआउट नेशन्स यानी उम्मीद से ज्यादा तरक्की करने वाले देशों में भारत के शामिल होने की संभावना 50-50 है। उनका मानना है कि भारत में तरक्की की पर्याप्त गुंजाइश बनी हुई है लेकिन उसे तेज आर्थिक सुधार अपनाने होंगे। बिजनेस भास्कर ने ब्रेकआउट नेशन्स और उनकी संभावाओं के साथ ही भारत से जुड़े कई पहलुओं पर उनसे चर्चा की। पेश है संक्षिप्त अंश :-

अपनी किताब ब्रेकआउट नेशन्स में आपने उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरक्की को अंतरराष्ट्रीय निवेश का इन देशों पर फोकस का नतीजा माना है। क्या 2003-07 के बीच जो तरक्की हुई, उसमें इन देशों की आर्थिक योजनाओं का कोई हाथ नहीं था?

यह सभी उभरते देशों के लिए लागू होता है। लेकिन अहम अंतर है विकास दर। मसलन तुर्की ने एक नई सरकार के नेतृत्व में 2001 और 2002 में कई अहम आर्थिक सुधार किए और इस वजह से इसकी विकास दर में खासा इजाफा दर्ज हुआ। जहां तक 2003 और उसके बाद भारत की आर्थिक विकास दर में इजाफे का सवाल है तो यह मुख्य तौर पर अंतरराष्ट्रीय पूंजी की वजह से था। इस ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बूम दिख रहा था। नब्बे के दशक के आर्थिक सुधारों की वजह से भारत ग्लोबल बाजार में तरलता के उफान का फायदा उठा सका। लेकिन 2003 से पहले ऐसे आर्थिक सुधार नहीं दिखे, जिनसे हम भारत की आर्थिक विकास दर में आई तेजी की वजह खोज पाते।

उभरते देशों में भारत की संभावनाओं पर आपने कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई है जबकि यह दुनिया की दूसरी तेज रफ्तार वाली इकोनॉमी है। युवा आबादी और एक बड़े उपभोक्ता बाजार को देखते हुए भी इसमें आंतरिक मांग के आधार पर तरक्की की काफी उम्मीद है। फिर भी आप भारत जैसे देश में ग्रोथ को झटका लगने की बात कर रहे हैं। वजह क्या है? भारत को क्या करना चाहिए?

मैंने भारत के बारे में निराशावादी राय जाहिर नहीं की है। ब्रेकआउट नेशन्स बनने की भारत की संभावना मैंने 50-50 माना है। पहली बार किताब जब आई तो कहा गया कि मैंने भारत के संदर्भ में निराशावादी रुख जाहिर किया है। इस पर मुझे अचरज हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान भारत से जो खबरें आ रही हैं उन्हें देख-सुन कर लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि ब्रेकआउट नेशन्स बनने की भारत की 50 फीसदी संभावना को ज्यादा ही आंका जा रहा है। लेकिन किताब जिस अवधारणा पर लिखी गई है, वह यह है कि ब्रेकआउट नेशन्स बनने के लिए उम्मीद से ज्यादा प्रगति दिखानी होगी।

जब मैंने यह किताब लिखी उस समय भारत के आठ फीसदी की दर से विकास करने की उम्मीद जताई जा रही थी। अब अर्थव्यवस्था का सेंटिमेंट खराब हो चुका है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भारत छह से सात फीसदी विकास दर भी हासिल कर सकेगा या नहीं। मेरा मानना है कि भारत में अभी प्रति व्यक्ति आमदनी काफी कम यानि 1500 डॉलर ही है, इसलिए सुधारों की गुंजाइश बनी हुई है।

आपने ब्राजील के कल्याणकारी कार्यक्रमों की आलोचना करते हुए कहा है वक्त से पहले कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की स्कीमों को अपनाने से एक समय में इसकी ग्रोथ रेट दो से तीन फीसदी के बीच रह गई। भारत में लगभग 40 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अशिक्षा है और स्वास्थ्य सेवाओं को बुरा हाल है। क्या ऐसे हालातों को बाजार के जरिये सुधारा जा सकता है?

अगर आप चीन के पिछले तीन दशक की ऊंची ग्रोथ रेट को देखें तो पाएंगे कि ये उन आर्थिक नीतियों का नतीजा रही हैं जिन्हें क्रूर पूंजीवादी कहा जा सकता है। मैं कल्याणकारी राज्य के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जितनी भी सफल अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें देखें तो पाएंगे कि कल्याणकारी योजनाएं एकबारगी लागू नहीं की गईं। देश की आय बढ़ने के साथ ही धीरे-धीरे लागू किया गया।

आपने कहा है कि चीन ने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की नीति छोड़ दी है। वहां खांटी पूंजीवाद का दौर है। क्या भारत में लोकतंत्र के रहते इस तरह की नीतियों के जरिये आगे बढ़ा जा सकता है?

अपनी किताब में मैंने इस सवाल की काफी गहराई से खोज की है कि ग्रोथ को बढ़ावा देने में लोकतंत्र बेहतर है या तानाशाही। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा इस चीज का फर्क पड़ता है कि नेतृत्व कैसा है। पिछले तीन दशकों में ऊंची विकास दर के 120 मामले दिखे हैं (ऊंची ग्रोथ का मतलब किसी भी एक दशक में वार्षिक विकास दर का औसत पांच फीसदी से ऊपर हो) । जिन देशों में ग्रोथ के ऊंचे मामले दिखे हैं उनमें आधे लोकतांत्रिक और आधे अधिनायकवादी शासन वाले देश थे। हम कल्याणकारी योजनाओं पर इस लिहाज से चर्चा करते रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जिताने में मदद करती हैं। लेकिन पिछले तीन साल में हमने देखा है कि कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद कांग्रेस या दूसरी सत्ताधारी पार्टियां चुनाव हारी हैं। दूसरी ओर, पिछले दशक के उत्तरार्द्ध में ऊंची ग्रोथ और कम महंगाई के दौर में सत्ताधारी पार्टियों को चुनाव में जीत भी हासिल हुई है।

आपने ब्रिक देशों को ब्रेकआउट नेशन्स की सूची से निकाल दिया है। रूस, चीन, ब्राजील और भारत की तरक्की के प्रति आप निराशावादी हैं? इन देशों को आगे क्या अड़चन हैं ?

इन बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बनी मेरी राय के पीछे कई वजहे हैं। चीन के बारे में मेरी राय निराशाजनक नहीं है लेकिन जितनी ऊंची उम्मीदें लगाई जा रही हैं उसका मैं कायल नहीं हूं। देखा जाए तो चीन अपनी ही सफलता का शिकार बन रहा है। भले ही आज चीन मध्य आय वाला देश बन गया है लेकिन अर्थशास्त्री यह मानने को तैयार नहीं हैं। ज्यादातर अर्थशास्त्री चीन में आठ फीसदी से ज्यादा विकास दर का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगले तीन से पांच साल में चीन 6 फीसदी की दर से ही विकास कर सकेगा। हालांकि छह फीसदी की ग्रोथ रेट कम नहीं है लेकिन चीन से ऊंची विकास दर की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए यह निराशाजनक हो सकता है। ब्राजील और रूस की विकास दर को लेकर मैं निराशावादी हूं। मेरा मानना है कि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को कमोडिटी बूम का फायदा मिला है। लेकिन अब बाजार में कमोडिटी की ओवरसप्लाई है। न तो ब्राजील और न ही रूस ने पिछले कुछ सालों में आर्थिक सुधार का कोई बड़ा कदम उठाया है ताकि उनकी विकास दर को रफ्तार मिल सके। मेरा मानना है कि इनमें से कोई भी देश भविष्य में तीन फीसदी से ज्यादा की जीडीपी दर हासिल नहीं कर सकेगा और इसलिए इनके ब्रेकआउट नेशन्स बनने की संभावना भी कम है। भारत के बारे में मेरी राय मिलीजुली है। मेरा मानना है कि ब्रेकआउट नेशन बनने के लिए भारत के मौके सबसे अच्छे हैं। क्योंकि अब भी भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है।

आपने इंडोनेशिया, तुर्की, चेक रिपब्लिक, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और ईस्ट अफ्रीका के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। यहां निवेशकों को ज्यादा रिटर्न हासिल होगा। तुर्की के प्रति आपने काफी उम्मीद जगाई है। आखिर इनकी तरक्की का क्या राज क्या होगा?

ब्रेकआउट नेशन्स की मेरी सूची में जो नाम हैं, उनसे लगाई जा रही उम्मीदें तार्किक हैं। ये आर्थिक सुधारों का कोई न कोई कदम उठाते दिख रहे हैं। ये सिर्फ पिछले दशक में किए गए सुधारों की वाहवाही पर मगन नहीं हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये देश निवेश के लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। इस समय पूरी दुनिया में एक लाख करोड़ डॉलर (एक ट्रिलियन डॉलर) वाली 15 अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें इंडोनेशिया और तुर्की शामिल होने जा रहे हैं। यह इस बात का मजबूत संकेत है कि मुसलिम लोकतंत्र कामयाब हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने जो सफलता हासिल की है उसकी वजह क्या है? तुर्की ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की अपनी दीवानगी पर लगाम लगाई और मध्यपूर्व और सोवियत यूनियन के पूर्व गणतंत्रों की ओर ध्यान केंद्रित किया। इसने देश के हर कोने में विकास का प्रसार किया। इसने समृद्धि के प्रसार को इस्तांबुल, इजमिर और अंकारा जैसे पुराने केंद्रों की तरफ ही नहीं मुसलिमों के हृदयस्थल अनातोलिया की ओर भी बढ़ावा दिया।

पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं यानि अमेरिका और यूरोप के बारे की संभावना पर आपकी क्या राय है?

अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2008 के बाद उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसकी वजहें हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था काफी प्रतिस्पर्द्धी है। ब्याज दरें कम हैं और कर्ज सस्ता है। इकोनॉमी के बेहतर प्रदर्शन की वजह आरएंडडी पर किया जाने वाला खासा खर्च भी है। दुनिया भर में आरएंडडी पर खर्च होने वाली रकम में एक तिहाई हिस्सेदारी अमेरिका की है। अमेरिकी इकोनॉमी इनोवेशन पर टिकी है। खास कर सॉफ्टवेयर के मामले में यह काफी मजबूत है। यही वजह है कि सोशल नेटवर्किंग से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सभी नई तकनीकें अमेरिका से आ रही हैं।

पश्चिमी अर्थव्यवस्था के और भी मजबूत गढ़ हैं। यूरोप में जर्मनी मजबूत अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों में जर्मनी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने न सिर्फ मैन्यूफैक्चरिंग की बुनियादी ताकत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं से होने वाली प्रतिस्पर्द्धा से बचा कर रखा है बल्कि काफी हद तक इसने इन देशों में विस्तार भी किया है। पिछले दशक के शुरुआती सालों में जर्मनी में हुए सुधारों की वजह से श्रम लागत की दरें यूरोप में सबसे कम रहीं। साथ ही जर्मनी ने सस्ते श्रम वाले पूर्वी यूरोपीय देशों में भी प्लांट लगाने शुरू किए। इसके आश्चर्यजनक नतीजे रहे। 1995 में जर्मनी की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 24 फीसदी थी और 2011 में यह बढ़ कर 45 फीसदी हो गई। इस वजह से जर्मनी में बेरोजगारी दर कम हो गई है और यह ट्रेड सरप्लस वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश हो गया।

आर्थिक सुधारों को रफ्तार न दे पाने की वजह से भारत में निवेशकों का विश्वास कम हो रहा है? आखिर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या करना होगा?

भारत में 2003 के बाद बड़े आर्थिक सुधार इसलिए नहीं हो पाए कि बहुत से लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि सुधार हो या न हों इस देश में तेज तरक्की होनी ही है। यह अति आत्मविश्वास का एक क्लासिक उदाहरण था। बहुत सी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा हुआ। इन देशों में आर्थिक सुधारों को सिर्फ संकट के समय अपनाया गया। इसीलिए ये देश अपनी ऊंची विकास दर को बरकरार रखते हुए विकसित देशों की पंक्ति में शामिल नहीं हो सके। इन्होंने सुधारों को संकट से निकलने का सहारा बनाया और फिर हालात सुधरते ही इसे बेहतर करने का मौका गंवा दिया। भारत को अब यह समझना जरूरी है कि पिछले एक दशक के दौरान हासिल आसान पूंजी अब हाथ आने वाली नहीं है और यह भी कि अब ग्रोथ के लिए इसे विदेशी निवेश की ज्यादा जरूरत है। इस देश में सरकार के खर्च कम करने होंगे ताकि निजी सेक्टर को ज्यादा संसाधन हासिल हो सकें।

देश में नीतिगत मसलों पर फैसले लेने में नाकामी और भ्रष्टाचार पर आप क्या कहेंगे? आर्थिक तरक्की को रोकने में ये किस तरह की अड़चनें पैदा कर रही हैं?

क्रोनी कैपिटलिज्म और भ्रष्टाचार से यह संदेश जाता है कि आर्थिक सुधारों से सिर्फ चंद लोगों को फायदा हो रहा है। कोरिया और ताइवान जैसी तेज रफ्तार इकोनॉमी में लोगों को यह अहसास होता है कि उन्हें बराबर के मौके मिल रहे हैं।

भारतीय उद्योगों के लिए विदेशी बाजारी में अधिग्रहण और निवेश की क्या संभावनाएं हैं?

भारतीय उद्योगों के लिए विदेशी बाजार में डाइवर्सिफाई करना कुछ हद तक जरूरी भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान भारतीय उद्योगों को यह लग रहा है कि भारत से ज्यादा विदेश में कारोबार करना ज्यादा आसान है। हालांकि भारत के विशाल घरेलू बाजार और आर्थिक विकास के इस बेहद शुरुआती दौर के मद्देनजर भारतीय कारोबारियों के सामने बाहर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस समय भारतीय कंपनियों के मुनाफे का दस फीसदी विदेशी बाजार से आता है। पांच साल पहले यह सिर्फ दो फीसदी था। भारत की शीर्ष कंपनियों में कम के कम 50 अब विदेशी बाजार पर निर्भर होती जा रही हैं। ये कंपनियां निर्यात, ग्लोबल कमोडिटी और अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण पर निर्भर हैं। यह निर्भरता बहुत ज्यादा है। भारतीय उद्योगों को अब घरेलू बाजार में ज्यादा निवेश करना जरूरी है ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ में इजाफा हो और ऊंची महंगाई की ओर ले जाने वाली अड़चनें भी दूर हो सकें।